भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4164

19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

लिथियम बैटरियों का स्वदेशी उत्पादन

4164. **सुश्री एस. जोतिमणिः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ई-वाहनों के लिए लिथियम बैटरियों का स्वदेशी निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो स्कीम या योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है: और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): भारत सरकार ने मई 2021 में "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" के अंतर्गत पीएलआई एसीसी स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें 2 वर्ष की अवधि के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए 50 गीगावॉट घंटा क्षमता के लिए 18,100 करोड़ रुपये का परिव्यय है। पीएलआई एसीसी स्कीम का उद्देश्य घरेलू सेल उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और सेल निर्माण की समग्र लागत को कम करना है।

50 गीगावॉट घंटा एसीसी क्षमता में से, 40 गीगावॉट घंटा एसीसी क्षमता पहले ही दो चरणों में चार लाभार्थी फर्मों को प्रदान की जा चुकी है। 40 गीगावॉट घंटा क्षमता का अंतिम उपयोग सामान्य एवं परिवर्तनीय (एग्नॉस्टिक) है और इसका उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल, रक्षा आदि के अलावा ई-वाहनों और स्थिर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित किसी भी अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्रिड स्केल स्थिर भंडारण (जीएसएसएस) अनुप्रयोगों के लिए 10 गीगावॉट घंटा क्षमता निर्धारित की गई है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

******